



राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जन- जन के साथ, विकास और अंत्योदय का मार्ग

ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों

का
शुभारम्भ

17 सितम्बर, 2025

शिविरों में होने वाले प्रमुख कार्य

♦ ग्रामीण सेवा शिविर ♦

- रास्ते खोलना, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामान्तकरण।
- लम्बित नोटिसों की तामीली एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना।
- मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र एवं स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना, किसान गिरदावरी एप द्वारा गिरदावरी करवाना।
- दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10 हजार और गांवों का बीपीएल सर्वे।
- पशुओं की जांच, इलाज एवं टीकाकरण।
- विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य।
- वृक्षारोपण, नमो वन को विकसित करना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्य।
- क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाडी, छात्रावासों एवं सड़कों के सुधार के कार्य।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्य।
- पीएमजेवाई कार्ड बनाना एवं वितरित करना एवं बीज मिनी किट वितरण।
- PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत गतिविधियाँ।
- NFSA अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, सदस्यों की ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना एवं UDID कार्ड बनाने से सम्बंधित कार्य।
- महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना।
- जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।

♦ शहरी सेवा शिविर ♦

- सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पोटों की समाप्ति।
- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत बंद पड़ी लाइटों को चालू करना।
- राईजिंग राजस्थान के प्राप्त निवेश प्रस्तावों हेतु भूमि चिन्हीकरण, स्वीकृतियाँ।
- जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एन. ओ. सी., ट्रेड लाईसेंस, साईनेज लाईसेंस, सीवर कनेक्शन, ओ. एफ. सी-मोबाइल टावर एन.ओ.सी./ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र आदि जारी करना।
- नमो पार्क को विकसित करना एवं सड़क मरम्मत/पेच वर्क के कार्य करना।
- आवारा पशुओं को पकड़ना।
- पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर, विकसित करना।
- नालियों की मरम्मत, फेरोकवर व मैन हॉल्स की मरम्मत, सीवर लाईन के लीकेज की मरम्मत।
- पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना एवं लम्बित प्रकरणों को ऋण वितरण करना।
- कृषि भूमि के पर बसी आबादियों में लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र, नामान्तरण एवं नाम हस्तातन्तरण।
- निकायों की योजनाओं में विक्रय आवंटित भूमि/भूखण्ड के लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे (आवंटन नीति, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट के पट्टे, नियम 1974 के नियम 18 से 19 में आवंटित भूमि को छोड़कर)।
- अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि।

विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

सलाम, जगदीप छोकर साहब

दिनांक 12 सितंबर 2025 को प्रोफेसर जगदीप छोकर 81 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए। पाठकों में से संभवतया कई इस नाम से अपरिचित होंगे और यह सोच रहे होंगे कि मैं इन पर संपादकीय स्तंभ क्यों लिख रहा हूं?

इसलिए, पहले उनके जीवन के बारे में जानकारी देना उपयुक्त होगा। जगदीप छोकर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और भारतीय रेल में कुछ समय तक नौकरी की। इन्होंने इसके बाद व्यवहार संगठन विषय में अमेरिका से एम बी ए और पीएचडी की। इसके बाद वे शैक्षिक जगत में आ गए और 1985 से 2006 तक आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे। इनके चयन के पीछे की कहानी है कि आई आई एम, अहमदाबाद के तत्कालीन निदेशक आईजी पटेल, ने उन्हें संदेश भेजा कि वे साक्षात्कार के लिए आए। उन्होंने उत्तर भेजा कि उन्हें उसी हॉटल में उहराया जाए जिसमें पटेल उहरे हुए हैं एवं उसी श्रेणी का विमान यात्रा का क्रियाया दिया जाए जिसमें पटेल यात्रा करते हैं। छोकर का आत्मविश्वास और स्वाभिमान देखकर उन्हें बिना साक्षात्कार के ही आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। सन् 2005 में उन्हें आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक पद का प्रस्ताव दिया गया, किंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वे कुछ समय तक आई आई एम अहमदाबाद के कार्यवाहक निदेशक अवश्य रहे।

अहमदाबाद में काम करते हुए छोकर और उनके साथियों ने महसूस किया कि राजनीति में पारदर्शिता का नितांत अभाव है तथा मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इस बारे में किसी की जवाबदेही भी नहीं थी।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने 1999 में अपने 10 अन्य साथियों के साथ एक संगठन ए डी आर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की स्थापना की। इस संस्था ने जगदीप छोकर के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गुजरात चुनाव में सभी उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई। उस समय, उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता एवं उनकी अपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी किसी को प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए, मतदाताओं के लिए अपने क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवारों का चयन करना कठिन होता था।

इसके लिए छोकर ने ए डी आर के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कानूनी जानकारी में दक्षता प्राप्त करने के लिए उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से रीटायरमेंट से पहले कानून की पढाई भी की और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करने में सफल रहे कि उम्मीदवारों के सम्बन्ध में कई आवश्यक जानकारियां नामांकन दाखिल करते समय मांगी जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सन् 2004 के चुनाव से निर्वाचन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नामांकन प्रस्तुत करते समय संबंधित उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र के साथ में अपनी शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति एवं उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। चुनाव में पारदर्शिता एवं शुचितता लाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह सब केवल एक व्यक्ति के अनवरत संघर्ष और प्रयास का ही फल था, और उस व्यक्ति का नाम था जगदीप छोकर।

आज प्रत्येक उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति और उसके विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। छोकर ने ए डी आर के माध्यम से उम्मीदवारों

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा । उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिए। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

सारी आवश्यक सूचना प्रदान करने का काम इस व्यक्ति ने किया।

इन्होंने प्रत्येक राजनीतिक दल के लेखों का भी परीक्षण किया और जनता के सामने लाए कि किस दल को किन्ना पैसा मिला और उन्होंने उसका किस प्रकार से उपयोग किया? इलेक्टोरल बॉड योजना के संबंध में भी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में छोकर में ही प्रस्तुत की जिसे अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक मानकर निरस्त किया गया।

हाल ही जो याचिका बिहार में एसआई आर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, उसमें भी पहले याचिका कर्ता जगदीश छोकर थे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि जब किसी मतदाता या राजनीतिक दल ने कोई विरोध नहीं किया है तो, ए डी आर जैसी संस्था दिल्ली में बैठकर ‘डेटा माईनिंग’ कर रही है, जो सही नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति को लगन ही थी कि जो आंकड़े चुनाव आयोग से ही उपलब्ध होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार से विश्लेषण करके उन्हें इस रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया कि वह समझ सके और तय कर सके कि कौन सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व ठीक तरह से कर पाएगा ?

इन्होंने आई आई एम अहमदाबाद से सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार यह काम अपने स्वयं के पैसे से किया, किसी काम के लिए कोई पैसा किसी से नहीं लिया। लोकतंत्र और राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए अनवरत काम करने वाला ऐसा व्यक्ति आज के युग में शायद ही कोई मिले। जगदीप छोकर की विशेषता यह भी थी उन्होंने अपने आप को कभी आगे नहीं रखा बल्कि अपने द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से ही वे जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहे। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि इस प्रकार के अप्राधिक पृष्ठ भूमि के व्यक्ति कैसे चुनाव में जीत जाते हैं तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे लोगों की पसंद नहीं होते। उम्मीदवार, राजनीतिक दल तय करते हैं न कि जनता।

चुनाव आयोग ने जब कोई जानकारी लोगों तक पहुंचाने में आनाकानी की तो उन्होंने न्यायपालिका का सहारा लिया।

जगदीप छोकर बहु आयामी के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने पक्षी विज्ञान में डिप्लोमा भी किया। वे अपनी बात बड़ी बेबाकी और स्पष्टता के साथ कहते थे। विभिन्न टीवी साक्षात्कारों में उन्होंने अपनी बात को सदैव पूरे आंकड़ों के विश्लेषण के साथ रखा। आज के युग में जहां सभी व्यक्ति केवल अपने ही बारे में चिंतित रहते हैं, वहां जगदीप छोकर ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने रीटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी और जवाबदेही, सुनिश्चित करने में खपा दिया।

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा।

उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिए। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

सलाम, छोकर साहब!

—अतिथि सम्पादक, राजन्नेत्र भाषावत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कृषि विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए राजस्थान सरकार क्या योजना रखती है, विखंडन या उन्नयन?



वीर बहादुर सिंह

एक कृषि विश्वविद्यालय को विखंडित कर पांच बना देने से शिक्षा और अनुसन्धान में गुणवत्ता नहीं बढ़ती और न ही संस्थानों में पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के आकर्षक भवन और उनमे खरीदकर रखी अनेक महंगी पुस्तकें, रिसर्च जर्नल्स और प्रयोगशाला में सजे महंगे उपकरण किसी भी प्रकार से शिक्षा और अनुसन्धान की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते यह सर्वविदित है।

विज्ञान में कहावत है कि यदि किसी स्थूल पदार्थ को पहले छोटे-छोटे और फिर उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कणों तक विखंडित किया जाय तो एक अदृश्य अणु प्राप्त होता है जो स्थूल अथवा भौतिक पदार्थ से सर्वथा भिन्न तो होता ही है अपितु स्थूल पदार्थ से अनेक भौतिक और रासायनिक गुणों में भी भिन्न होता है। ऐसा ही कुछ प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सरकार ने विगत वर्षों में किया है। मेरी अभी तक समझ नहीं आया कि राजस्थान प्रदेश की जो भी सरकारें आजादी के बाद बनीं उन्हें सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कृषि विश्व विद्यालयों के औचित्य के बारे में कभी ठीक से बोध ही नहीं हो पाया। अब तो कई दशक बीत गए लेकिन एक उचित बोध किसी के मस्तिष्क में अभी तक नहीं पनप सका है।

मेरा मानना है यह प्रदेश भेड़, ऊँट, बाजरा और मक्की तक ही अपनी सोच रखता था उसके आगे नहीं। अतः कृषि के बारे में एक बृहत सोच की परिकल्पना करना युक्तसंगत नहीं रहा। फिर भारतीय परिवेश में ऐसे अनेक समुदाय हैं जो पीढ़ीओं पुरानी अपनी परम्पराओं से इतने गहरे आबद्ध हैं कि उन्हें उस परिवेश में ही परम संतुष्टि मिलती है, शायद प्रदेश के लोगों की भी ऐसी ही मनोदशा है। उससे परे वे निकलना ही नहीं चाहते। विकास से भी वे आबद्ध नहीं होना चाहते लेकिन उसका भोग करने को आतुर रहते हैं।

वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का सूत्र पात हुआ था जिसके कारण देश में आज खाद्यान्न उत्पादन में बड़े अत्यभिर्भर होकर सरफल में है। पहले अमेरिका से पीएछ 480 योजना के अंतर्गत लाल रंग का गेहूँ हम भारतीयों को सरकारालय के लिए राशन की दुकानों से उपलब्ध करवाती थी। अनाज लेने के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर अनाज ले पाते थे। आज स्थिति बिलकुल उलट चुकी है यह स्थिति कैसे आई पिछली कुछ सरकारों ने इस पर मनन किया? अनाज उत्पादन में तो देश शास्त्रिकों की ही अन्य उत्पादन पद्धतें आकर्षक, दूध, अंडे, मांस-मछली, विभिन्न तेल, कपास, आदि में भी देश काफी संतोषप्रद उत्पादन कर रहा है। यह सब और इससे सम्बंधित उत्पाद कृषि शिक्षा व् सतत अनुसन्धान और उत्तम बीजों के विकसित करने से संभव

अजमेर, (कासं)। वरुण सागर स्थित बोराज गांव में एक बार फिर पैँथर का आतंक नजर आया। रविवार रव रात पैँथर ने बाड़े में घुसकर गौँवश को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों के शोर मचाये पर पैँथर पास के पहाड़ों की ओर भाग गया, लेकिन गांव में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने सोमवार को वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैँथर को पकड़ने की मांग की है।

ग्रामीण गामा रावत ने बताया रविवार रव रात बोराज गांव में लेपेड़ एक घर के पीछे बाड़े में घुस गया था। लेपेड़ ने वहां पर बकरी और गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। हमले में गाय के बछड़े दम तोड़ दिया। जानवरों की आवाज सुनकर ग्रामीण नींद से जाग गये और उन्होंने देखा कि पैँथर गाय के बछड़े को खा रहा था। ग्रामीणों की आवाज सुनकर

हो सका है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसमें अपने कठोर परिश्रम और लगन से देश को वर्तमान स्थिति तक पहुँचाया है। सचिवालयों में बैठे प्रसाशनिक अधिकारी, जन प्रतिनिधि व मंत्री और मुख्यमंत्री संभवतः इस मूल सच्चाई से लगभग ढाई दशक से अनभिज्ञ हैं, और यह प्रभाव पीड़िओं के अंतराल से उत्पन्न और अधिक चौड़ा हुआ है जिसके परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। कृषि शिक्षा और अनुसन्धान लगभग ढाई दसक से अधोगति की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, कुछ ही समय बाद पहले जो ढांचा खड़ा किया था वह अणुओं में बिखर अदृश्य हो जायेगा। और फिर स्वामीनाथन और वर्गीज़ सरीखे वैज्ञानिक पुनः कृषि उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। देश के प्रधान मंत्री चहुमुखी किसान और कृषि विकास के पक्षधर हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि प्रदेश की सरकारें कृषि विकास शिक्षा में अवरोध डालने के लिए कैसे मायावी ताने वाने बुनती रहती हैं ?

राजस्थान सरकार किसी संसाधन को निर्मित करने के लिए नकल करने को तो आतुर रहती है लेकिन उसके उपरांत निष्क्रिय हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रदेश में कृषि विकास को गति प्रदान करने वास्ते कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने बावला उत्तरप्रदेश पंतनगर (अब उत्तराखंड) में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बनने के बाद ही राजस्थान के उदयपुर में भी वर्ष 1962 में दूसरा कृषि विश्व विद्यालय बना था जो अल्प समय में ही राजनीतिज्ञों के मल्लकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया और सब भविष्य के नर्त में समा गया। तब से फिर वर्ष 1987 में पृथक कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में विदेशी डॉक लेकर बनाया जा सका। इससे दौंचागत सुविधा तो बना ली गई परंतु आगे फिर सरकारी अफसरों की नसमझी से उसका विकास पलित्वत नहीं हो सका, फलस्वरूप गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा और अनुसन्धान अहिरावण की गिरफत में चले गए। विगत वर्षों से कोई हनुमान प्रदेश में पैदा नहीं हुआ जो तारणहार बनता।

सरकार ने बीकानेर स्थिति विश्व विद्यालय को कुछ वर्षों बाद ही विभाजित कर चार और कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जोबनर में बना दिए। ये सभी संस्थान भवनों में भले ही पूर्ण होते हों अन्य सुविधाओं यथा वांछित कृषि शिक्षक या विषय विशेषज्ञ व अनुसन्धान कर्ता संख्या में अभी पिछड़े तो हैं ही सभी अपने स्वरूपों के विखंडन का सरकारी इन्तजार भी कर रहे हैं। विखंडन पश्चात् इनके बचे स्वरूपों की क्या उपयोगिता होगी ये भविष्य बताएंगे? कोई जांच एजेंसी वर्ष 2001-2 में उपलब्ध अनुमोदित वैज्ञानिकों की संख्या का आज मौजूद संख्या से मिलान करे तो किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा और कर्णधार तब जवाब देने से मुंह छिपाते दिखेंगे।

सरकार ने जब-जब कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में खोले, घोषणा पश्चात् सरकार ने एक तदर्थ कुलपति की नियुक्ति कर दी साथ ही सचिवालय ने एक एक्ट और उसके साथ कतिपय मोटे मोटे उपनियम (स्टैट्यूट्स) बनाकर गजट में नोटिफिकेशन करवा कर वििबत सञ्चालन आरम्भ करवा दिया।

बोराज गांव में फिर पैँथर का आतंक, ग्रामीणों में दहशत

- पैँथर ने बाड़े में घुस कर गौवंश को शिकार बनाया, ग्रामीणों के शोर मचाये पर पहाड़ों की ओर भाग गया**
- ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैँथर को पकड़ने की मांग की**

पैँथर वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि गाय ने एक माँह पहले ही बछड़े को खसका है। पैँथर के हमले में बछड़े की मौत हो गई। सुबह तक गाय बछड़े के पास खड़ी रही और उसे छोड़ने को

कोंग्रेसी और बीजेपी सरकारें एक के बाद एक पूर्णरूप से दोषी हैं। आगे भविष्य बताएगा जब करोड़ों के उपकरण भी धूल चाटकर और जंग खाकर बिना उपयोग में लिए कवाड़ में बिकेंगे। उन सबकी खरीद पर काफ़ी व्यय सरकार, कृषि अनुसन्धान परिषद् और विश्व बैंक कोष से अनुदान स्वरूप मिलता धन खर्च हुआ है। सब व्यर्थ हो गया बीस पच्चीस वर्षों में। धन के अपव्यय की ऐसी मिसाल इस प्रदेश में ही मिलती है अन्य जगह नहीं। इसका मूल कारण जवाबदेही की कमी। हम सरकार में बिराजमान सुप्रीम सचिवों को तो जवाब देह उठरा नहीं सकते भले ही वे किसी मसले पर अनुमति देर से दें या बिलकुल न दें? विश्वविद्यालय भवनों से नहीं चलते वे ज्ञानी और अनुभवी विषय विशेषज्ञों से संचालित होते हैं और विश्वविद्यालय भी चापलूसी से नियुक्त कुलपति और वैज्ञानिकों से भी नहीं चला करते उनके लिए विद्वान्, कर्मठ और ईमानदार लोग ही सही संचालन कर सकते हैं।

बड़ी विडम्बना एक और है कि छात्र वर्ग अब निर्बिचार हो चुका है उसे कोई मतलब नहीं कुछ भी होता रहे जबकि उसके अधिकारों पर यह सीधा कुठारा घात है उसे तो बस डिग्री मिलनी चाहिए जो उसे वर्तमान में मिल ही जाती है। लगभग पाँच दसक पूर्व बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र और युवाओं के सहयोग से देश में भूचाल ला दिया था यह विदित हो ही तब के एक रेल मंत्री ने भी ऐसा चक्का जाम किया था कि स्टेशन पर डिब्बे और इंजन भी नदरद गये थे और स्टेशन लगता सम शान स्थला अब को लीडरशिप नहीं है खाना तो वही है आबोहवा भी वही फिर अपना भला बुरा देखने की प्रवृति का लोग हमारे युवाओं में क्यों हो गया? उनकी शिक्षा पर व्यय माता-पिता करते हैं फिर वे भी सब उदासीन ?

कृषि शिक्षा व अनुसन्धान के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में नियमानुसार दो कमेटी यथा डिपार्टमेंट समिति ,बोर्ड ऑफ़ स्टडीज समिति या कोर्स समिति होती हैं वैसे तो इसमें सदस्यता निर्धारित है परन्तु विभागाध्यक्ष के निर्देश पर सभी लोग इनमें भाग लेते हैं। यही वो जगह है जहाँ विषय पढ़ाने पर आधी किसी भी बाधा पर सभी दृष्टिओं से संवाद होकर हल निकाला जाकर सुचारु पढ़ाई संभव होती है। वर्तमान में जब वांछित संख्या में विषयवार विशेषज्ञ ही न हों तो फिर न तो कोई समिति संभव है और न कोई सम्बाद। लिहाजा विषय की पढ़ाई जैसे तैसे लचर-पचर चलती रहती है। पढ़ाने वाले ने जैसा संभव बन पडा पढ़ा दिया, गुणवत्ता बढ़ाने की कोई संभावना नहीं रहती। उपरोक्त समितियां होते हुए छोटे अनुसन्धान के लिए भी सम्बाद कर कुछ रिसर्च भी सम्पादित संभव हो जाती है। और कभी बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला बनाकर उनके लिए वांछित आर्थिक मदद के लिए किसी बड़ी संस्था को अप्रोचित कर दिए जाते हैं। ध्यान रहे विभाग के स्थाई वैज्ञानिक हैं इस कार्य को संपन्न करने के योग्य माने जाते हैं। इसलिए एक विभाग उत्पति के लिए ऐसे काम करता है जैसे फौज में सिपाही अपनी यूनिट के लिए इसलिए विभागों की सख्या में अपार कमी से संस्था के सञ्चालन हेतु बने एक्ट आदि नियमावली के प्रावधान

मनन करें, विचारें, साथिओं से सम्वाद करें और यदि आप उपरोक्त कथन से सहमत हैं तो और क्या और कैसे किया जा सकता है? ध्यान रहे सभी कुछ सरकार पर छोड़ने की अपेक्षा सरकार को देश हित और कृषि शिक्षा हित के लिए उचित तरीके से बाध्य करना और उत्तरदायी बनाना हम सब का उत्तरदायुत्व है।

—प्रो. वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, उदयपुर, राजस्थान

अवैध बजरी खनन व परिवहन जारी, प्रशासन मौन

बौली/बामनवास, (निसं)। क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी अवैध बजरी खनन व परिवहन बेधड़क चल रहा है। क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्ग व ग्रामीण सड़कों पर बजरी से भरे डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली व छोटे ट्रक हर समय दौड़ते नजर आते हैं, इनके कारण अनेकों दुर्घटनाओं में लोग जान गवा चुके हैं

गौरलतब है कि सबसे बड़ी बात यह है बौली नगर के मुख्य सड़क मार्ग निवाड़, बौली व लालसोट मार्ग पर पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बौली पुलिस ने 14 व 15 सितंबर को कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर ट्राली जब्त की हैं। पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया कि उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, हैड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह व हैड कांस्टेबल सुनील दत्त के नेतृत्व में गठित अलग-अलग तीन टीमें ने रामदेव निराहा के पास खिरनी व ग्राम बहनौली, पीपलवाड़ाव चांदा की झोपड़ियां से दरिश् देकर अवैध बजरी खनन व परिवहन करते तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया है। चावल व मलिक पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए।

स्वतः राज्य सरकार के हाथ आपस्त हो चुके हैं।

सड़क से बटोरे शिक्षकों से ऐसी सब अपेक्षायें नहीं की जा सकती कि वे विभिन्न समितिओं के सदस्य के रूप में छात्रों के लिए कोई निर्णय करें इसके लिए नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है ऐसे टीचर वास्तव में विश्व विद्यालय पर एहसान करते हैं जिससे संस्था को कहने को होजाता है कि छात्रों की पढ़ाई ठीक से जारी है। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी स्तर पर अकादमिक कौंसिल भी होती है जिसमे अक्रॉस फैकल्टी विभिन्न संकाय / विषयों के सदस्य होते हैं कुछ विषय विशेषज्ञ अन्य संस्थानों से भी नामित किये जाते हैं ताकि उनके अनुभव का लाभ भी प्राप्त हो सके। अकादमिक अयन के लिए ये तीन समीतिअं आवश्यक समझी गई हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों के बिगाड़े गए संतुलन से विश्व विद्यालय इन समितिओं के कार्य को कैसे सम्पादित कराते हैं? यह जांच का मुद्दा है।

शिक्षा के सुचारु प्रबंधन के लिए संस्था हेड की नियुक्ति कुलपति बिना किसी नियम कायदों के करते हैं स्वाभाविक है ऐसे में जिस प्रकार सरकार कुलपति नियुक्त करती है, कुलपति भी अपने स्वयं के विवेक से महाविद्यालय अधिष्ठाता और निदेशक अनुसन्धान व् निदेशक प्रसार शिक्षा और विभागाध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं यह सब वांछित और अनुमोदित योग्यताओं की अनदेखी कर संभव होता है।

कुछ ही हो, नियम कायदे और योग्यता अनुभव को दरकिनार कर जब ऐसे कार्य किसी शिक्षा संस्थान में होते हैं तो संशय शंकाएं और स्टफफ में अवशयोग बलवती होने लगता है और परणिति आखिर में बताता चलू कि कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा कृषि विश्व विध्यालयों के लिए मानक प्रमाणिकता (एक्रीडिटेशन) की बाध्दता आज थोथी बन चुकी है वर्तमान स्तिथि में इसका औचित्य प्रश्नात्मक है। विश्व विद्यालय स्तर पर ऐसी मानक वाध्दता स्नातकोत्तर विषय पढ़ाने के लिए भी होती है जिसे विश्व विद्यालय की पी.जी. कौंसिल विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रदान करती है।जिससे व्यक्ति स्नातकोत्तर कक्षाएं पढ़ाने के लिए अनुमोदित होता है। बाकी कुछ पक्ष कृषि शिक्षा संस्थानों में व्याप्त मसलों पर मैंने वर्णित कर दिए हैं, जिन्हें समय रहते सरकारी और विश्वविद्यालय स्तर पर सुधारना आवश्यक है। सरकार यदि अपना दृष्टिकोण बदलने में सक्षम नहीं है तो अन्य विकल्प, कृषि शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को बजट सहित हस्तांतरित कर दे, इसी में प्रदेश की पैशाई है।

मनन करें, विचारें, साथिओं से सम्वाद करें और यदि आप उपरोक्त कथन से सहमत हैं तो और क्या और कैसे किया जा सकता है? ध्यान रहे सभी कुछ सरकार पर छोड़ने की अपेक्षा सरकार को देश हित और कृषि शिक्षा हित के लिए उचित तरीके से बाध्य करना और उत्तरदायी बनाना हम सब का उत्तरदायुत्व है।

—प्रो. वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, उदयपुर, राजस्थान



पंडित अनिल शर्मा

मिथुन, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से प्रातः 6:46 तक है। कुमार योग प्रातः 6:46 से आरम्भ होगा। आज भद्रा दिन 12:57 से रात्रि 12:23 तक है। आज आश्विन संक्रांति, सूर्य कन्या में रात्रि 1:47 पर प्रवेश करेगा। आज दशमी का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:19 से 10:50 तक, लाभ-अमृत 10:50 से 1:53 तक, शुभ 3:25 से 4:36 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:27

राशिफल

मंगलवार 16 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 6:46 तक, वारियान योग रात्रि 12:34 तक, वणिज करण दिन 12:57 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:29 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज यमघट योग सूर्योदय से प्रातः 6:46 तक है। कुमार योग प्रातः 6:46 से आरम्भ होगा। आज भद्रा दिन 12:57 से रात्रि 12:23 तक है। आज आश्विन संक्रांति, सूर्य कन्या में रात्रि 1:47 पर प्रवेश करेगा। आज दशमी का श्राद्ध है। **श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर 9:19 से 10:50 तक, लाभ-अमृत 10:50 से 1:53 तक, शुभ 3:25 से 4:36 तक। **राहूकाल:** 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:27



मेप

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।



तुला

नवीन कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।



वृष

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। स्वाभावित धन प्राप्त हो सकेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।



वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तित्व खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरियां/पेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मानसिक तनाव नहीं रहेगा। मन:स्थिति में सुधार होगा।



धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।



कर्क

व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। मन में असंतोष और भय बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।



मकर

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।



कन्या

व्यावसाय



He Invented The Zoo But Tested On People First

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

वक्फ अमैंडमेंट एक्ट के तीन विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेष अधिनियम के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की तीन प्रमुख धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एंजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं पर संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन पर निर्णय आने तक उन्हें स्थगित रखा जाएगा।

अधिनियम में जिलाधिकारी को दिए गए अत्यधिक अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा: “कलेक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे सत्ता के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा कोई निर्णय नहीं होता, तब तक किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाली धारा स्थगित की जाती है।”

नए कानून के अनुसार, जिलाधिकारी को वक्फ संपत्ति के

- **चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने जिन तीन प्रावधानों पर रोक लगाई है, उनमें पहला कलैक्टर को दिए गए “अत्यधिक” अधिकारों से संबंधित है।** कोर्ट ने कहा, कलैक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह “सेपरेशन ऑफ पावर्स” के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक इस प्रावधान पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस धारा को स्थगित किया जाता है।
- **दूसरा प्रावधान वक्फ बोर्ड तथा केन्द्रीय वक्फ काउन्सिल में गैर मुस्लिम सदस्यों से संबंधित था, कोर्ट ने इसे भी स्थगित कर दिया है।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है।**

स्वामित्व से जुड़े विवादों में अंतिम निर्णायक बना दिया गया था। अधिनियम में कहा गया था: “यदि जिलाधिकारी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि संपत्ति (पूरी या आंशिक रूप से) विवादित है या सरकारी संपत्ति है, तो उस हिस्से को वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा न हो जाए।”

इस प्रावधान का मुस्लिम संगठनों ने विरोध करते हुए कहा था कि इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध दावों की बाढ़ आ जाएगी।

पीठ ने यह भी कहा कि किसी वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-

मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी कहा कि कानून में जो प्रावधान था कि “कोई व्यक्ति जिसने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो, वही वक्फ घोषित कर सकता है,” उसे भी स्थगित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “ऐसे किसी तंत्र के बिना यह प्रावधान मनमानी शक्ति के प्रयोग का कारण बन सकता है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका रख हमेशा यह मानकर चलता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुकूल होता है, और किसी अधिनियम में हस्तक्षेप

“बहुत ही दुर्लभ मामलों में” किया जाना चाहिए।

1995 के वक्फ कानून में संशोधन, जिसे अप्रैल में संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, के बाद देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने इसे संविधान-विरोधी बताते हुए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने साजिश करार दिया था। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कई वक्फ संपत्तियां भूमि विवादों और अतिक्रमण में फंसी हैं, और नया कानून इन्हें सुलझाने के लिए है।

वक्फ संशोधन अधिनियम को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आयकर रिटर्न जमा करने की डैड लाइन नहीं बढ़ाई गई है’

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डैड लाइन 30 सितम्बर किए जाने की वायरल खबर को फर्ज़ी करार दिया

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15, सितंबर। अगर आपने भी यह वायरल हुई खबर देखी है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है, तो सतर्क हो जाइए, यह दावा फर्ज़ी है।

इनकम टैक्स विभाग ने पुष्टि की है कि आधिकारिक अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितम्बर ही है।

वॉट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक भ्रामक संदेश में दावा किया गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है।

वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि पहले से बढ़ाई गई 15 सितम्बर की तारीख के बाद कोई

- **हाल ही में वॉट्सएप और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि आयकर रिटर्न की डैड लाइन, जो पहले 15 सितम्बर थी, को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है।**
- **वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी नोटिस जारी नहीं किया गया है।**

आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। विभाग ने इस फर्ज़ी प्रेस विज्ञापन को ऑनलाइन साझा किया है, जिस पर “फेक” (फर्ज़ी) की लाल मुहर लगी हुई है ताकि करदाताओं को सचेत किया जा सके।

एक बयान में विभाग ने कहा: “एक फर्ज़ी खबर प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि (जो पहले 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई) को और बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनी हुई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक “इनकम टैक्स इंडिया अपडेट” पर ही भरोसा करें।”

15 सितम्बर की अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है, जो टैक्स (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले का हाई कोर्ट ने केस बंद किया

जयपुर, 15 सितंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी प्रकरण में, एसीबी

- **अदालत ने कहा एसीबी ने अपराध को प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है।**

की ओर से पेश एफआर के आधार पर केस को बंद कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश भरत मालानी व अशोक सिंह की अपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एसीबी ने स्वयं ही प्रकरण में अपराध बनना प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है। ऐसे में एफआईआर को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पांच साल पहले पेश याचिका में एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

88 वर्षीय महिला की पेंशन क्यों रोकी?

जयपुर, 15 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 88 वर्षीय महिला को अतिरिक्त राशि देने को आधार बनाकर उसकी फैमिली पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी और एसबीआई के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकला बाबेल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाई कोर्ट ने पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी व एसबीआई के शाखा प्रबंधक से जवाब मांगा।**

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति कार्मिक विभाग से सितंबर, 1994 में सहायक सचिव पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उनकी पेंशन आरंभ हो गई। वहीं अगस्त, 2008 में पति का निधन होने पर विभाग ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन देना शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया कि 26 दिसंबर, 2024 को कोषागार अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पत्र लिखकर जानकारी दी कि उसे 8.76 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हो गया है और संबंधित बैंक को कोषागार के पक्ष में इस राशि का डीडी जमा कराने को कहा गया है।

याचिका में कहा गया कि इस पत्र के आधार पर बैंक ने गत जनवरी माह से उसकी पेंशन का भुगतान रोक लिया। याचिका में कहा गया कि वह 88 साल की महिला है और पूरी तरह इस पेंशन पर आश्रित है। इसके अभाव में बीते करीब नौ माह से उसका जीवन यापन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बिहार के एस.आई.आर. में हम अलग से निर्णय नहीं दे सकते’

सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था है, अतः हम मानते हैं कि सभी कानून व कायदों का अनुसरण कर रहा होगा, नई मतदाता सूची बनाने में

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15, सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन-एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई गैरकानूनी तरीका पाया गया, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।

बेंच ने यह स्पष्ट किया कि वह केवल बिहार के मामले में टुकड़ों में राय नहीं दे सकती, बल्कि यह निर्णय देशभर में होने वाले सभी एसआईआर प्रक्रियाओं पर लागू होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि वह यह मानकर चलती है कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, एसआईआर की कवायद में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है, जिसमें बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर बहस होगी। इससे पहले, कोर्ट ने 8 सितम्बर (सोमवार) को आदेश दिया था कि इस समय चल रही

- **पर, अगर यह पाया गया कि सूची फाइनल करने की प्रक्रिया में कुछ गैरकानूनी तरीके अपनाये गये हैं, तो सूची बनाने की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी।**

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, चुनाव आयोग के अधिकारी, आधार कार्ड को उस बारहवें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, नाम व पते के प्रमाण के लिए।**

एसआईआर में, आधार कार्ड को बिहार के मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट का यह हस्तक्षेप तब आया, जब उसे ऐसी शिकायतें मिलीं कि चुनाव अधिकारी पहले के निर्देशों के बावजूद आधार को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर रहे थे। न्यायमूर्ति सुर्यकांत एवं जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि भले ही आधार “नागरिकता का प्रमाण नहीं” हो सकता, लेकिन यह पहचान और निवास का “वैध दस्तावेज” है। वह सुनवाई उन “आशंकाओं और आरोपों” के संदर्भ में हो रही है,

जो “विपक्षी दलों” ने उठाए हैं कि प्रक्रिया के तहत असली मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के हटा दिए जा रहे हैं।

विपक्ष का कहना है कि यह एसआईआर प्रक्रिया “अनुचित सफाई अभियान” है, क्योंकि नाम जोड़ने के लिए जिन 11 दस्तावेजों की जरूरत बताई गई है, उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था, जबकि यह अन्य दस्तावेजों की अपेक्षा आम नागरिकों के पास सामान्यतः होता ही है। चुनाव आयोग ने “18 अगस्त” को उन 65 लाख लोगों के नामों की सूची जारी कर दी थी, जो एसआईआर प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाये गये हैं।

‘कोई भी भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता था’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को मजबूर किया था, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने दावा किया है कि एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी की दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के दबाव में खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ा।

रविवार को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने केवल खेल पर ध्यान केन्द्रित रखा। खेल के दौरान बल्ले और गेंद के बीच की प्रतिस्पर्धा को छोड़कर दोनों टीमों के बीच कोई मेलजोल नहीं हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाता भारतीय टीम का पूर्व नियोजित निर्णय था,

- **स्पोर्ट्स तक चैनल से एक वार्ता में सुरेश रैना ने दावा किया कि एक भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मन से तैयार नहीं था।**
- **भारतीय टीम की अनिच्छा पूरे मैच के दौरान नज़र आई। जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात करना तो दूर औपचारिक “हैंड शेक” तक नहीं किया।**

जिससे सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाक टीम हैरान रह गई। अब यह भी सामने आया है कि भारतीय खिलाड़ी यह मैच खेलना ही नहीं चाहते थे। स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत में पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार, टीम का कोई भी खिलाड़ी एशिया कप खेलना नहीं चाहता था। एक तरह से वे मजबूर थे क्योंकि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट खेलने के लिए हमी भर दी थी।” रैना ने कहा, “मुझे दुख है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर सुर्यकुमार यादव और उनकी टीम से व्यक्तिगत राय ली जाती, तो वे मना कर देते।

किसी का मन नहीं था खेलने का।” पहलगाम आतंकी हमला, और उसके बाद शुरू हुए “ऑपरेशन सिंदूर” के चलते, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक अपूर्व

निचले स्तर पर पहुंच गए। दोनों देशों के बीच के तनाव को महेनज़र रखते हुये, यह भी सवाल उठने लगे थे कि इस साल एशिया कप होगा भी या नहीं। लेकिन अंततः बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट बोर्डों ने टूर्नामेंट कराये जाने पर सहमति जताई।

बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की मंजूरी दिए जाने के बाद, मैच के बहिष्कार की मांग भी उठी थी। सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। फिर भी भारतीय टीम ने शोर को नज़रअंदाज़ कर निर्धारित मैच खेलने का साहस दिखाया।

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मैदान पर जीत तो हासिल की ही, साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया।

‘वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही’

नयी दिल्ली, 15 सितंबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि

- **संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। यह निर्णय लोकतंत्र के हित में है।**

श्रीधर अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है। रिजिजू ने वक्फ संशोधन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

#LANGUAGE

Words With A History

The Curious Origins of ‘Knockoff,’ ‘Bootleg,’ and ‘Coppers’



Bootlegging contraband.



Language is a living archive of human history, shaped by war, trade, rebellion, crime, and culture. Many of the words that we use casually today have origins that reach back centuries, often tied to very specific social or political contexts. Take, for instance, the terms knockoff, bootleg, and coppers. At first glance, they may seem like everyday slang, but behind them lie stories of piracy, prohibition, and policing. Their histories not only reflect how people lived but also how they broke the rules, and how society responded.

The word ‘knockoff’ is today most commonly associated with imitation goods: counterfeit designer bags, fake sneakers, cheap tech gadgets made to look like premium brands. But its roots are industrial and pragmatic. In the early 20th century, the phrase likely emerged from the idea of ‘knocking off’ a product, either by copying its design or quickly reproducing a cheaper version. In factories and workshops, to ‘knock off’ something could also mean to produce it with haste, often with little regard for authenticity or quality. Over time, this evolved into the modern notion of a knockoff: something that looks like the real deal but lacks its craftsmanship, originality, or legitimacy. While today the term is often used in a consumer context, its origin speaks volumes about early industrial mass production and the thin line between innovation and imitation.

Moving from counterfeit goods to contraband, the term ‘bootleg’ has a far more rebellious and shadowy past. Its most famous association comes from early 20th-century America, during the Prohibition era (1920-1933), when the sale and manufacture of alcohol were banned across the United States. People found creative ways to smuggle liquor, and one of the most common methods

involved hiding bottles inside the tall boots worn by traders and smugglers. Hence, the term ‘bootlegging’ was born, literally referring to liquor concealed in one’s bootleg. While it began as a description of alcohol smuggling, it soon expanded to include any kind of illicit or unauthorized goods, particularly media like music, movies, and later, software. Even today, when someone refers to a ‘bootleg’ version of a concert or a film, they’re using a term that was born in the dark corners of speakeasies and back-alley deals.

Then, there’s the term ‘coppers,’ a nickname for police officers, especially in Britain and the United States. Its origin is slightly murky, but two main theories prevail. One suggests that it comes from the copper buttons and badges that 19th-century British and American police officers wore as part of their uniforms. These gleaming copper accessories made them easy to identify and may have led to the nickname. Another theory traces the word back to the verb ‘to cop,’ meaning to seize or arrest, a word derived from the Latin *capere*, meaning ‘to take.’ In this sense, a ‘copper’ is one who ‘cops’ criminals, one who takes catches, or arrests wrongdoers. While ‘coppers’ is now largely considered an old-fashioned term, kept alive in detective novels, vintage films, and British crime shows, it remains a nostalgic echo of an earlier era of law enforcement.

Though, the words have evolved in meaning over time, these words carry within them fragments of history, whispers of prohibition, piracy, protest, and policing. They remind us that language is never static. It grows from human experience, often shaped by the tension between law and lawlessness, between imitation and authenticity, between order and rebellion. And that’s what makes it so endlessly fascinating.



Carl Hagenbeck opened his Tierpark Hagenbeck in Hamburg, Germany, in 1907. Decades earlier, the impresario had exhibited indigenous humans in conditions that replicated their home environments.

● Verna Mohon

Carl Hagenbeck opened his Tierpark Hagenbeck in Hamburg, Germany, in 1907. Decades earlier, the impresario had exhibited indigenous humans in conditions that replicated their home environments.

At the turn of the 20th century, the great zoological gardens of Paris, London and New York City would have been hardly recognizable by today’s standards. Animals, large and small, those that had evolved to sprint across plains and live half their lives submerged in water, were confined in rows of tiny, barren cages lined with metal bars. “They were often on their own and had nothing natural in their enclosures,” says Karen S. Emmerman, an expert on Animal Ethics at the University of Washington. At a time when it was difficult to keep exotic animals alive, let alone healthy, in such con-

strained conditions, giving the creatures freedom to roam outdoors was viewed as a death sentence.

But Carl Hagenbeck, a German animal trader and entertainment impresario, had a different vision of what zoos could be. These animals, he argued, should be able to engage in innate behaviours ‘in an environment which differed as little as possible from their own natural environment.’ Ibexes needed mountains to climb. Lions needed grottos for bathing.

When Hagenbeck opened his Tierpark Hagenbeck in Hamburg, Germany, in 1907, it was unlike any zoo seen before. Instead of small indoor cages, he ‘recreated the natural landscape of faraway places,’ says Nigel Rothfels, a historian at the University of Wisconsin-Milwaukee and the author of *Savages and Beasts: The Birth of the Modern Zoo*. Hagenbeck built ‘living habitats,’ large outdoor enclosures with sturdy fake rocks and shallow artificial pools. He replaced cage bars with moats and dug deep pits that could be observed from above. He created the perception that the animals, while not exactly free, were living authentic lives that mirrored their experiences in the wild.

Visitors loved the innovations,

and over the next several decades, the so-called Hagenbeck revolution spread, transforming zoos around the world in the image of Hamburg’s Tierpark. More than a century later, ‘living habitats’ are still a hallmark of modern zoos. But while Hagenbeck traded, trained and showcased animals his entire life, it wasn’t elephants or lions that led him to recognize the need to display exotic species in quasi-natural ecosystems. Hagenbeck first tested his ideas on human beings.

Before there were zoos, there were menageries, collections of living animals that were housed in the gardens of European royalty. Once reserved for aristocrats, these menageries opened to the public in the 17th and 18th centuries; commoners could also attend performances hosted by itinerant showmen who traveled from town to town with exotic species in tow.

By the mid-19th century, zoological gardens had shifted from manifestations of elite status to symbols of power and progress for European cities, growing rapidly by the light of the Industrial Revolution. Because zoos required global acquisition networks and extensive funds to maintain, building them became an expression of a city’s political and economic influence. Soon, they were popping up across the continent and in many urban centers in the United States, too. (The Smithsonian’s National Zoological Park, now the National Zoo and Conservation Biology Institute, opened in Washington, D.C. in 1891.)

“If you’re a legitimate city by the end of the 19th century, you better have a zoo,” says Rothfels.

Hagenbeck supplied the majority of the wild animals that ended up in Europe’s first public zoos. Lanky, with a stoic demeanor, traced his interest in zoos to his youth, recalling in his autobiography how local fishermen once gave his father, a fishmonger, at least six seals they had accidentally caught in their nets. A lover of animals with a small personal menagerie of his own, Hagenbeck’s father built two large wooden tubs and opened his doors to visitors, charging each 1 shilling for a look. The family business took off from there.

In 1859, at age 14, Hagenbeck assumed responsibility for his father’s animal trade, expanding the



Wilhelm II of Germany speaks to individuals on display in a ‘human zoo’ at Tierpark Hagenbeck in 1909.

He Invented The Zoo But Tested On People First

Despite the deaths and his supposedly firm resolve ‘never to arrange human exhibitions again,’ Hagenbeck continued putting people on display well into the 1880s. By the end of the decade, human zoos had taken on a life of their own. They found a welcome audience at world’s fairs, beginning with the 1889 Exposition Universelle in Paris. Scholars estimate that over just 50 years in the late 19th and early 20th centuries, 20,000 to 25,000 indigenous people were exhibited in ‘living habitats’ in the West.

#DID-YOU-KNOW



Carl Hagenbeck, circa 1890.

company’s networks across Africa, Asia and the South Pacific, just as a new surge in colonial exploration was carving up the globe. Soon, he was importing giraffes, antelopes, ostriches, rhinoceroses, panthers, cheetahs, birds, buffaloes and dozens of other species for zoos across Europe. In 1872, the American entertainment mogul P.T. Barnum purchased animals worth £3,000 (nearly \$400,000 today) from Hagenbeck for his upcoming traveling show. Hagenbeck claimed that Barnum dealt exclusively with him for the rest of his life.

For close to two decades, the German businessman dominated the exotic animal trade. But the one-two punch of an economic downturn and the rise of a new generation of traders in Europe and the U.S. eventually led Hagenbeck down a less-traveled path. It wasn’t just the beasts of distant lands that fascinated audiences in the West, but also the curious, never-before-seen human communities caught in the crosshairs of imperial expansion. In 1874, when a friend suggested that Hagenbeck display indigenous Sami herders, alongside his next shipment of Scandinavian reindeer, the impresario needed no convincing.

Indigenous people from around the world had been displayed as spectacles in Europe since the 16th century, typically in staged performances or as sideshow acts. But Hagenbeck valued authenticity above all else. He felt that the public would be more interested in watching the Sami carry out the routines and rituals of their daily lives than in attending a contrived or dramatized show, and he wasn’t wrong.

Reflecting on the ‘huge success’ of his first ethnographic exhibition, Hagenbeck wrote, “I attribute this mainly to the simplicity with which the whole thing was organized and to the complete absence of all vulgar accessories. There was nothing in the way of a performance.”

For this initial 1875 display, Hagenbeck brought two families, the Rastis and the Nielsons, to Hamburg along with their 31 reindeer and their essential items:



Hagenbeck poses with a chimpanzee and three lion and tiger cubs.



Five Kavésgar whose remains were repatriated to Chile in 2010.



Abraham Ulrikab, an Inuit from Labrador, Canada, who died of smallpox while appearing in a Hagenbeck show in Europe.

crates full of tools, skates and snowshoes, as well as sledges and several dogs to pull them. In an open yard behind his home, the Sami raised their tents and hung them with tanned reindeer hides sewn with sinew. They dressed in long deer skin coats and pointed fur caps, and they laid out areas for fixing equipment and preparing meals. Audiences reportedly loved to watch the families milk their reindeer, which milled about the enclosure as if it were their familiar Arctic Circle habitat.

“All Hamburg came to see this genuine ‘Lapland in miniature,’” Hagenbeck later wrote. To the impresario and his visitors, the

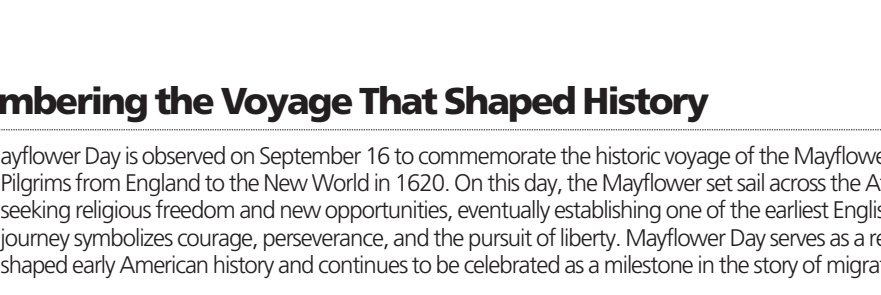
indigenous families were ‘unspoiled children of nature,’ representatives of a simple, romanticized people who had long ago disappeared from European shores.

For the few weeks, they were on display at Hagenbeck’s estate, the Rastis and the Nielsons attracted so many visitors that the businessman wasted little time in recruiting the next guests for his *völkerschau* (‘people show’), what scholars today refer to as ‘human zoos.’ He went bigger this time, importing a large group of Sudanese men (and one woman, Hadjide) alongside massive black dromedaries and other species native to their homeland in 1876.

Hagenbeck staged similar Sudanese ‘caravans,’ as he called them, multiple times, attracting 62,000 people to his Berlin show in a single day, according to Rothfels. He followed up this act by displaying six Greenlandic Inuit adults and children in 1878 and eight more Inuit from Labrador, Canada, in the fall of 1880. The later exhibition ended in tragedy when every member of the group died of smallpox, a disease that Hagenbeck’s team had failed to vaccinate them against.

After briefly swearing off human displays, Hagenbeck was soon back at it, this time with a group of indigenous Kawésgar people, who’d been abducted by a German ship captain in Chile’s Tierra del Fuego archipelago in 1881. Hagenbeck displayed the 11 men, women and children virtually naked, refusing to give them European-style clothing that would protect them from the cooling autumn temperatures. Unlike previous groups displayed by Hagenbeck, the Kawésgar were not accompanied by tools or domestic animals, adding to a problematic perception pushed by the day’s pre-eminent anthropologists: that the tribe was a holdover from the Stone Age, made up of ‘primitive’ people who’d survived only because their homeland was inhospitable and remote.

“They could have progressed further if the adversity of their environment had not repressed them so much that they remained at



Remembering the Voyage That Shaped History

ayflower Day is observed on September 16 to commemorate the historic voyage of the Mayflower, the ship that carried the Pilgrims from England to the New World in 1620. On this day, the Mayflower set sail across the Atlantic with over 100 passengers seeking religious freedom and new opportunities, eventually establishing one of the earliest English settlements in America. The journey symbolizes courage, perseverance, and the pursuit of liberty. Mayflower Day serves as a reminder of how this voyage shaped early American history and continues to be celebrated as a milestone in the story of migration and settlement.



Water birds in a naturalistic zoo habitat.

the lowest level of social life,” claimed German physician and anthropologist Rudolf Virchow. Observing them, he believed, was akin to going back to prehistoric times to observe humanity’s ancestors.

Hagenbeck only halted the show after five of the Kawésgar died, likely of tuberculosis and measles. He lifted the bodies of the dead to a Swiss university for study and sent the living back to Chile. One died on the journey home. The Swiss university repatriated the remains of the five kidnapped Kawésgar to the Chilean government in 2010.

Despite the deaths and his supposedly firm resolve ‘never to arrange human exhibitions again,’ Hagenbeck continued putting people on display well into the 1880s. By the end of the decade, human zoos had taken on a life of their own. They found a welcome audience at world’s fairs, beginning with the 1889 Exposition Universelle in Paris. Scholars estimate that over just 50 years in the late 19th and early 20th centuries, 20,000 to 25,000 indigenous people were exhibited in ‘living habitats’ in the West.

The subtext of these displays wouldn’t have been lost on audiences of the time. Told that indigenous people were evolutionarily inferior to white Europeans and Americans, visitors accepted the idea that colonialist progress would soon condemn these groups to extinction.

“Whatever their disagreements, humanitarians, missionaries, scientists, government officials, explorers, colonists, soldiers, journalists, novelists and poets were in basic agreement about the inevitable disappearance of some or all primitive races,” writes Patrick Brantlinger in *Dark Vanishings: Discourse on the Extinction of Primitive Races, 1800-1930*. “Savagery, in short, was frequently treated as self-extinguishing.”

No longer the only showman trading in indigenous people, Hagenbeck complained that there was too much competition in people shows to make a decent profit anymore. Meanwhile, as the frenzy for human spectacles waned, the animal market once again stabilized. While Hagenbeck never completely abandoned the human zoo, his Tierpark in Hamburg boasted plenty of space



Indigenous people on display at the 1889 Exposition Universelle in Paris.

to display indigenous people, he reinvested his energy into trading, training and showing exotic animals.

For these captive creatures, extinction seemed similarly inevitable. But unlike indigenous communities whose cultures and ways of life were considered beyond saving by the Western world, advocates of animal zoos came to believe that their most important role was not demonstrating ‘colonial power over colonized places,’ says Emmerman, but preventing the species they displayed from disappearing forever.

The ‘living habitat’ championed by Hagenbeck laid the foundation for zoos to begin presenting “themselves as more than merely recreation, places whose mission was described as conservation,” an often-invoked ethos.

public about issues like habitat loss and extinction became a primary goal.

Today, zoos are the subject of much debate, with supporters touting the work they have done to save various species and critics questioning the effectiveness of their conservation efforts. There is no doubt, however, that zoo animals are better off today than they were before the introduction of Hagenbeck’s innovations. The development of an accreditation process in the early 1970s by the Association of Zoos and Aquariums further advanced standards for zoos, establishing a set of best practices to ensure that captive animals receive proper care.

Despite his complicated legacy, Hagenbeck is widely considered the progenitor of this shift in viewing exotic animals not as objects, but as living beings with needs and intellectual abilities.

“Before Hagenbeck, zoological gardens often struggled to convince the public that it was not so bad to be an animal at the zoo,” Rothfels writes in *Savages and Beasts*. Ever since Hagenbeck, animals have not been collected merely for reasons of science or education, or even really for recreation, animals have been put in zoos increasingly because they are nice, healthy, safe places to be and because the animals, we are told, might be better off there than in the real ‘wild.’

rajeshsharma1049@gmail.com

#REAL TOYS

Meet the First Barbie With Type 1 Diabetes

The new doll boasts a pink continuous glucose monitor to track blood sugar levels and a pink insulin pump

Mattel collaborated with leading diabetes organization Breakthrough T1D to design the first Barbie doll with Type 1 diabetes. Barbie has worn many hats, literally and figuratively since her debut in 1959. The iconic doll has traveled to space, performed surgery, run for the nation’s highest office and competed in the Olympics. Now, for the first time, Barbie is showing what it’s like to live with Type 1 diabetes, an often-invisible illness.

Mattel debuted the Barbie as part of the Fashionistas line, which seeks to reflect the diversity of the world by showcasing dolls with different skin tones, body types and medical conditions. The new doll is outfitted in a blue polka dot ensemble, a nod to the blue circle, the global symbol of diabetes awareness. She comes with realistic tools that people with Type 1 diabetes rely on every day: a pink continuous glucose monitor (CGM) to track blood sugar levels, a smartphone with an app synced to the CGM and a pink insulin pump to deliver doses of the hormone. Each detail aims to normalize the tools of diabetes care and ensure that the children who use them feel represented in the toys that they play with.

Mattel developed the doll in close collaboration with Breakthrough T1D, a leading diabetes research and advocacy nonprofit. The toy company also consulted focus groups and volunteers who live with Type 1 diabetes.

The new Barbie aims to give children with the condition a higher level of visibility and understanding. “They feel seen. They feel heard. They feel empowered,” Pam Morrisroe, chief marketing officer for Breakthrough T1D, tells CBS News’ Nancy Chen. “You don’t



know immediately when somebody has Type 1 diabetes necessarily, unless you see their devices,” Morrisroe says. She describes the doll as “a conversation starter” and adds that “it’s a great way to educate.”

Type 1 diabetes has no known cure, but recent research suggests stem cell treatments might one day be able to reverse the condition. A 2025 study found that 10 of 12 people infused with a stem cell-based treatment no longer needed insulin one year later.

Type 1 diabetes is a chronic autoimmune condition in which the pancreas produces little to no insulin, a hormone necessary for processing blood sugar. Contrary to some media misrepresentations, Type 1 diabetes is not linked to diet or lifestyle, and its exact cause is unknown. The disease requires constant vigilance, as blood sugar levels can shift based on everything from physical activity and food intake to sleep patterns and stress.

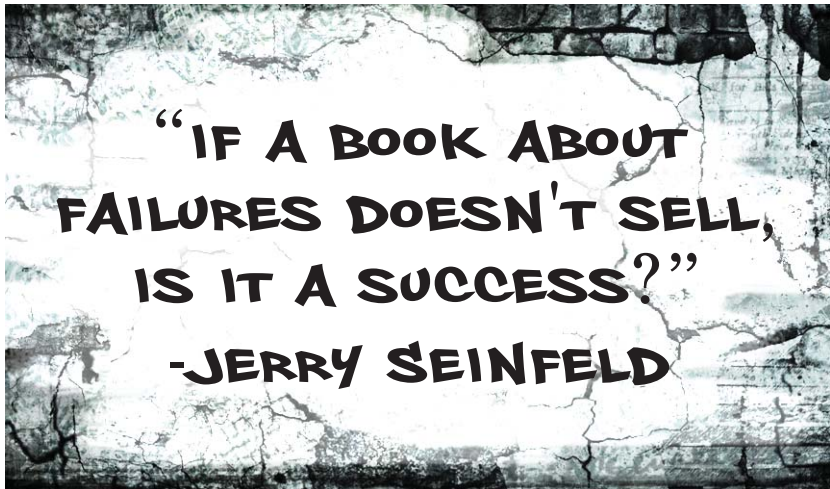
In 2021, around 1.7 million adults in the United States reported that they’d been diagnosed with Type 1 diabetes and used insulin to treat the condition; this number is projected to rise to about 2.3 million by 2033. Type 2 diabetes, in which the body can’t properly use insulin, is far more common than Type 1 and is often caused by lifestyle factors such as a lack of physical activity.

In addition to launching the new doll, Barbie also honoured model Lila Moss and Peloton instructor Robin Arzon, both of whom live with Type 1 diabetes, with their own one-of-a-kind dolls. As Moss, who has walked international runways while wearing her insulin pump with pride, says in a statement, “To be able to now see Barbie dolls with (Type 1) diabetes, and to receive a Barbie doll that visibly looks like me even wearing her patches, is both surreal and special.” Arzon, for her part, says, “I’ve found a lot of purpose in advocating for people with the condition and educating others about it because knowledge is power, especially for young minds.” The doll, which is priced at \$10.99, joins a growing range of inclusive toys sold by Mattel. The Barbie Fashionistas collection already includes dolls with hearing aids, prosthetic limbs, Down syndrome and vitiligo, among other traits.

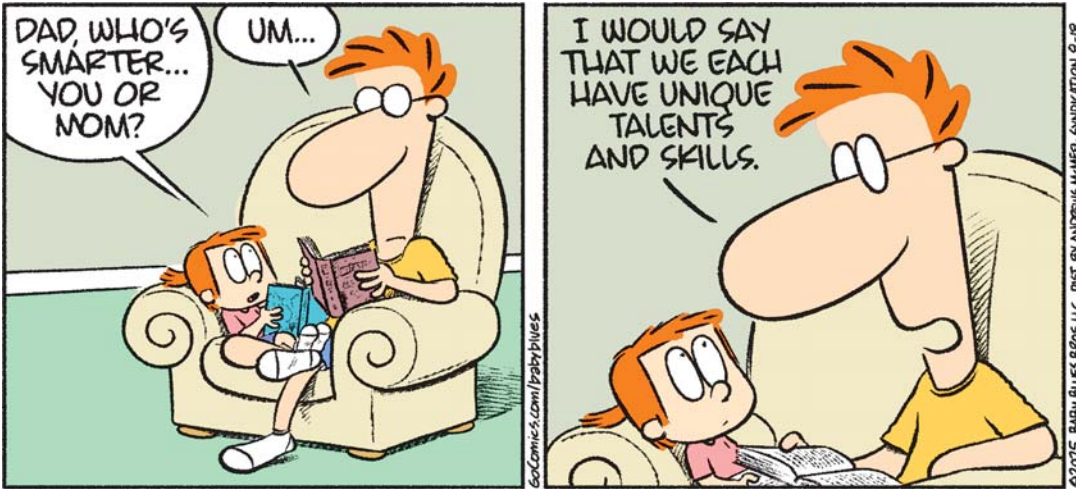
Educators are taking notice of the new product. A preschool teacher told Morrisroe that she preordered the doll to use as a learning tool in her classroom. Two of her students have Type 1 diabetes. “Representation matters so much,” Morrisroe tells CBS News. “Visibility matters so much.” As Devin Duff, a spokesperson for Mattel, tells CNN’s Brenda Goodman, “We know that increasing the number of people who can see themselves in Barbie continues to resonate.”



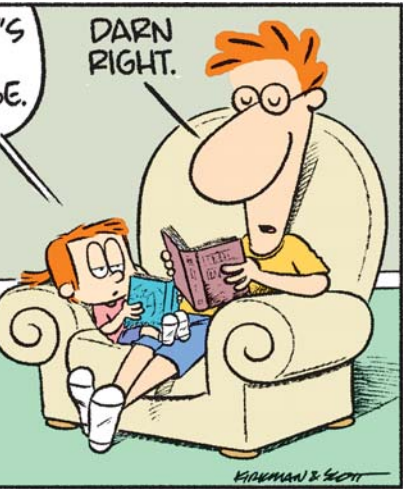
THE WALL



BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott



ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

सरकार ने 2 2 2 आर.ए.एस. का तबादला कर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया

वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू बने मुख्यमंत्री भजनलाल के विशेषाधिकारी

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। राजस्थान सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) के 222 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और बीकानेर की 9 यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। साथ ही वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू को मुख्यमंत्री भजन लाल का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अशोक कुमार योगी वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के विशिष्ट सहायक (एसए) के पद पर पोस्टिंग दी गई है। शुद्ध के लिए यूपु और मिलावटी वस्तु के छापों से चर्चा में आए पंकज ओझा को खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त से हटाकर उन्हें गौ-पालन निदेशक के पद पर लगाया गया है। गौरतलब है कि पंकज ओझा ने फूड सेफ्टी विभाग में रहते बड़े स्तर पर छापेमारी की थी। इसके साथ ही नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त के साथ-साथ कई उपायुक्तों का तबादला किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में भी अतिरिक्त आयुक्त लगाते हुए कई नये उपायुक्तों को लगाया गया है। इस आदेश में संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों का भी तबादल किया है। जिसमें दिनेश कुमार जाँगिड को

- खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा को गौ-पालन निदेशक बनाया
- जयपुर ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार बने स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक
- हैरिटेज निगम के अतिरिक्त कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह यादव को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में लगाया
- जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त समेत कई नये उपायुक्त लगाए, ग्रेटर-हैरिटेज के उपायुक्त भी बदले

सहाकारिता विभाग से पशुपालन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी है। असलम शेर खान को जल संसाधन विभाग से अल्पसंख्यक मामला विभाग में संयुक्त सचिव, नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। आनंदीलाल वैष्णव को प्रसारण निगम के सचिव से गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर लगाया है। खान विभाग की संयुक्त सचिव आशु चौधरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार पद पर लगाया गया है। राजपाल सिंह का सीईओ जिला परिषद कोटा से कोटा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पद पर तबादला किया है।

कोटा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भावना शर्मा को अब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कुमार को अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग से महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में रजिस्ट्रार के पद पर लगाया है। राजस्व अपील अधिकारी सुरेश कुमार नवल को भरतपुर विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर लगाया गया है। अरविंद सारस्वत को खान विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार को स्थानीय निकाय विभाग में अतिरिक्त निदेशक बनाया

गया है। सीमा कुमार की जगह नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से तबादला करके नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हैरिटेज नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव का तबादला करके उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) के अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं हैरिटेज निगम के उपायुक्त युगान्तर शर्मा को अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जयपुर दक्षिण के पद पर लगाया है। प्रवीण कुमार द्वितीय, बिजेन्द्र सिंह और राजेन्द्र कुमार द्वितीय को हैरिटेज निगम में उपायुक्त, नीलम मीणा को ग्रेटर निगम में उपायुक्त के पद पर लगाया है। इसी तरह प्रतिभा पारीक को जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त के रित्त पद पर लगाया है। रविन्द्र कुमार शर्मा, देविका तोमर, खेमाराम यादव, ओम प्रभा, अश्वदीप बराड, सीमा खेतान और पुखराज कासोटिया को जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त लगाया है। साथ ही महावीर सिंह द्वितीय को जेडीए में प्राधिकृत अधिकारी के पद पर जिम्मेदारी सौंपी है। आर.ए.एस. गोपाल सिंह को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड जयपुर में सचिव तथा डॉ. अशोक कुमार चतुर्थ

को उपसचिव के पद पर लगाया है। इसके अलावा घुसकांड में एसीबी में ट्रेप हो चुके पुष्कर मित्तल को झालावाड़ के मनोहर थाना में एसडीएम लगाया है। साथ ही एपीओ चल रही कश्मीर कौर रॉन को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के रजिस्ट्रार पद पर पोस्टिंग दी गई है। डॉ गुंजन सोनी को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर और ममता यादव को बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। सावन कुमार चायल को आयुर्वेद विभाग के उपसचिव से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के रजिस्ट्रार पद पर लगाया है। झुंझुनू एसडीएम पंकज शर्मा का तबादला वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव को स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव, मत्स्य यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लोकेश कुमार मीणा को राजस्थान उपनिदेशक के पद पर लगाया है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार हरतिमा को उपायुक्त सीएडी बीकानेर लगाया। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की रजिस्ट्रार सतिता को जिला आवकरी अधिकारी कोटा के पद पर लगाया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। इसके लिए प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदशील प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और

दिव्यांगजनों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विभागीय स्तर पर निगरानी की जाए और परिवाहियों को समाधान की जानकारी समय-समय पर दी जाए। उन्होंने आपसी समझाइश से विवादों के समाधान को प्राथमिकता देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह

सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस जनसुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, मनरेगा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याएं उठाई गईं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया स्मारिका का विमोचन

जयपुर (कासं)। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों को समाहित कर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। इस स्मारिका में ग्रेटर निगम के वार्ड 84 में हुए बहुआयामी विकास कार्यों के साथ जन उपयोगी एवं अन्य जानकारी का भी समावेश किया गया है।

स्मारिका का प्रकाशन चेयरमैन पार्षद वार्ड 84 अभय पुरोहित द्वारा करवाया गया। जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर किया।

इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावट, लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता एवं पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा, अभय पुरोहित,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेटर निगम जयपुर के चेयरमैन अभय पुरोहित द्वारा सांगानेर के विकास कार्यों पर तैयार स्मारिका का विमोचन किया।

एसएफएस डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष किशन लाल छतानी, सीए ललित चांदगोटिया, श्री दिगंबर जैन अध्यक्ष डॉ. राजेश जैन काला समाज एसएफएस की निवर्तमान उपस्थित रहे।

उधारी चुकाने का झांसा दे महिला से दुष्कर्म

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में एक परिचित ने महिला से रुपए उधार लिए और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पंडिता ने आरोपी से नकदी लौटाना का दबाव बनाया तो आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी की धमकी से परेशान महिला ने थाने पहुंच घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पंडित महिला के बयानों के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला का आरोप है कि परिचित होने के कारण दोनों में बातचीत थी और आरोपी का घर पर आना-जाना था। आरोपी ने वर्ष 2019 में महिला से उधार रुपए लिए थे। जिसके बाद वो दो-तीन सात पर नकदी लौटाने के लिए झंसे देता रहा। आरोपी ने पंडिता को प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

शेखावाटी की हवेलियां हमारी अनमोल धरोहर : मुख्यमंत्री भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़ी जाए, जिला कलेक्टर करें सुनिश्चित : भजनलाल शर्मा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल एवं अद्वितीय धरोहर हैं। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत की सुरक्षा व रखरखाव के लिए हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनू, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया है। इन हवेलियों को हैरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होमस्टे और टूरिज्म हब के रूप

में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़ी जाए। शेखावाटी क्षेत्र की धरती अपने आप में कला, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। ऐसे में शेखावाटी क्षेत्र आज पर्यटन में सिरमौर बन रहा है। इस वर्ष के छह माह में शेखावाटी के तीन जिलों सीकर, झुंझुनू और चूरू में लगभग एक करोड़ 90 लाख देशी पर्यटक और 33 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक आए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दे रही है। इसी तरह खादूरथामजी मंदिर एवं

सालासर बालाजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को कुल 30 हैरिटेज प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाणपत्र हवेलियों को संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामाढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतडी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में सामने आया कि आरोपित नशे के पैसों के लिए चोरी करते थे। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

दो मोबाइल चोर गिरफ्तार

जयपुर। रामनगरिया थाना पुलिस ने दो मोबाइल चोरों सौरभ उर्फ सागर मीना (21) निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल खानाबदोश जगतपुरा और सलातख खान (22) निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल लुनियावास खोह नागोरियान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित नशे के पैसों के लिए चोरी करते थे। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

रक्तदान अमृत महोत्सव में 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 75 देशों में 7500 से अधिक रक्तदान शिविर लगाएंगे



ग्रेटर नगर निगम जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन किया जायेगा। भारत सहित 75 देशों में 7500 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन बुधवार को करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा।

अभियान का लक्ष्य 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर सेवा का अद्वितीय उद्घाटन प्रस्तुत करना है। देशभर में 4 हजार रक्त बैंक, 5 हजार डॉक्टर, 25 हजार लैब टेक्नीशियन और 1 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़कर सेवा में भाग ले रहे हैं। यह जानकारी मंगलवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावट, लक्ष्मी इंडिया फाइनंस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद, जयपुर परिषद् अध्यक्ष रवि छाजेड, राष्ट्रीय एमबीडीटी टीम एवं जयपुर कैप के संयोजक सुरेंद्र नाहटा, जयपुर संभा के प्रभारी करण नाहटा, जयपुर परिषद् के मंत्री शरद बरडिया ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में दी।

उप महापौर पुनीत कर्णावट ने

बताया कि यह मुहिम रक्त की जरूरत है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, रेलवे पुलिस फ़ोर्स तथा एन.एस.एस सहित अनेक संस्थाएं इस अभियान का सहयोग कर रही हैं।

केन्द्रीय नेताओं जैसे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, पिप्लू गोयल आदि का समर्थन प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और खेल मंत्री मनसुख माण्डविया ने पूरे देश में अभियान का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। लक्ष्मी इंडिया फाइनंस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद ने बताया कि पिछले वर्षों में परिषद् ने 10 लाख से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किए हैं। वर्ष 2022 में 6149 शिविरों के माध्यम से 2.5 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर ब्रिटिश संसद में रिकॉर्ड दर्ज कराया गया था। जयपुर शहर में 126 रक्तदान स्थलों पर कैप लगाए जाएंगे।

सीएसटी के हथ्ये चढ़ा मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स तस्कर

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच में एसपीटी) ने मानसरोवर थाना इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 87.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त किए हैं। पुलिस ने जब्त

- 21 लाख रु. की 87.70 ग्राम ड्रग जब्त
- जोधपुर से खरीदकर जयपुर में सप्लाई करता था आरोपी

एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपये आंकी है। फिलहाल आरोपी तस्कर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई करने वाले तस्कर कमलेश कुमार (21) निवासी चित्तलवान जिला जालौर हाल मानसरोवर जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी के पास से 87.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी भी जब्त किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित अवैध मादक पदार्थ एमडी प्रेम बागड़ी निवासी जोधपुर से खरीदना बताया है। जो अपनी महिला मित्र के सहयोग से जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर सप्लाई करता है। पुलिस आरोपित तस्कर से अवैध मादक पदार्थ एमडी की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है।

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। आमजन को चाहिए कि वे बिना हेलमेट चलने वालों को टोकें और उन्हें सुरक्षा के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बात केवल चालान की नहीं, बल्कि जीवन बचाने की है। उपमुख्यमंत्री सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग (सप्तामा) अभियान के समापन एवं अभियंता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आमजन की सक्रिय भागीदारी से ही सड़क सुरक्षा अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। उन्होंने अभियान में अभियंताओं, विशेष रूप से महिला अभियंताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह पहल ऐतिहासिक है। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री और उनकी टीम को उपमुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि यह अभियान जनता के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है।दिया कुमारी ने कहा कि यह अभियान आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सभी सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सोशल मीडिया



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया ।

अकाउंट्स पर इस अभियान के प्रमुख बिंदु साझा करें, ताकि यह व्यापक स्तर पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में दो दिन सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों का भीतिक निरीक्षण करें और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट कहा

कि अब केवल फाइलों पर हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा। यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो आगे कोई चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री ने बताया कि 9 अगस्त से 15 सितंबर तक चले इस अभियान में प्रदेश के 1097 संस्थानों के 4.18

लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। करौली जिले ने 112 संस्थानों के 41,031 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर पहला स्थान प्राप्त किया। मास्टर ट्रेनर कविता हरिण, रेणू मीणा और अधिशाषी अभियंता हरिनारायण मीणा को उपायुक्त दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा सीकर, डूंगरपुर, झुंझुनू और जयपुर के अधिकारियों तथा अभियान में सक्रिय दो वाहन चालकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, मुख्य अभियंता टी.सी. गुप्ता, नोडल अधिकारी शिल्पा श्रीमाल, विभागीय अधिकारी, महिला मास्टर ट्रेनर और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

- दिया कुमारी ने कहा “सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाएं”

लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। करौली जिले ने 112 संस्थानों के 41,031 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर पहला स्थान प्राप्त किया। मास्टर ट्रेनर कविता हरिण, रेणू मीणा और अधिशाषी अभियंता हरिनारायण मीणा को उपायुक्त दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा सीकर, डूंगरपुर, झुंझुनू और जयपुर के अधिकारियों तथा अभियान में सक्रिय दो वाहन चालकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, मुख्य अभियंता टी.सी. गुप्ता, नोडल अधिकारी शिल्पा श्रीमाल, विभागीय अधिकारी, महिला मास्टर ट्रेनर और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

